विचार बिन्दु

विनम्रता की परीक्षा समृद्धि में और स्वाभिमान की परीक्षा अभाव में होती है।
–आदित्य चौधरी

बजट के आंकड़ों में राज्य की माली हालत की तस्वीर

बजट को समझने के लिए उसके दस्तावेजों में जाना पड़ता है जो वित्त मंत्री अपने भाषण के साथ सदन के पटल पर रखती है। आम तौर पर मीडिया के लोग बजट भाषण से ही अपना काम चला लेते हैं। मगर उसमें वही होता है जो सरकार दिखाना चाहती है। बजट राज्य की वित्तीय हालत का आईना होता है जिसका विश्लेषण दो वर्ष बाद सीएजी की रिपोर्ट में सामने आता है। एक समय था जब स्थानीय अर्थशास्त्री बजट प्रस्तुत होने के कुछ दिनों बाद ही उसके दस्तावेजों के आंकड़ों का विश्लेषण किया करते थे। अब वह परंपरा नहीं रही। अब इसकी किसी को परवाह भी नहीं है। आंकड़ों में छुपी सच्चाई को देखना लोकतान्त्रिक व्यवस्था में आम जन का अधिकार होता है, किन्तु आंकड़ों का विश्लेषण थोड़ा तकनीकी होता है जिसे हर एक के लिए समझना संभव नहीं होता। सरकार से अपेक्षा होती है कि वह राज्य की अर्थव्यवस्था की पूरी सही परिपेक्ष्य में बजट भाषण में प्रस्तुत करे। लेकिन बजट भाषण महज ऊपर का आवरण होता है, जबकि असली सच्चाई बजट के साथ के दस्तावेजों में होती है। मिसाल के तौर पर राइज़िंग राजस्थान की धूम के बीच राज्य के बजट से यह जानना कि मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर 2023-24 में 12.85 प्रतिशत थी, वह 2024-25 में घट कर 11.77 प्रतिशत हो गई तथा 2025-26 में वित्त वर्ष समाप्त होने तक और गिर कर 10.24 प्रतिशत रह जाएगी। 2011-12 की स्थिर कीमतों पर भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर में 2024-25 के मुकाबले 2025-26 में गिरावट दर्ज हुई है। थोक मूल्य सूचकांक एक बड़ा माप है जो कीमतों में उतार-चढ़ाव को ट्रैक करता है, और एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह 2024 में 1.13 परसेंट की बढ़ोतरी दिखाता है जिसे प्रशासन मामूली मानता है। इसी प्रकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आम घरेलू जरूरत की चीजों और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। साल 2025 में, उसने राज्य के औद्योगिक कामगारों के लिए महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की है। इसी प्रकार इस आर्थिक समीक्षा में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर की मौजूदा और स्थिर कीमतों (2011-12)पर ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रोथ रेट में गिरावट बताई गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में मौजूदा कीमतों पर यह वृद्धि दर 10.63 प्रतिशत थी जो 2024-25 में गिर कर 9.65 प्रतिशत रह गई तथा उसके 2025-26 में और तेज गिरावट के साथ 3.47 प्रतिशत रह जाने वाली है। स्थिर कीमतों पर भी 2025-26 के अनुमानों के अनुसार यह 0.22 प्रतिशत तक नीचे चली जाने वाली है। साल 2025-26 में, एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर ने राजस्थान के ग्रॉस वैल्यूएडेड में मौजूदा कीमतों पर 25.74 परसेंट का योगदान दिया है, जो साल 2011-12 में 28.56 परसेंट था। इसका अर्थ हुआ कि कृषि क्षेत्र का राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में भूमिका कम होती जा रही है जो और कम होती जाने वाली है। लेकिन विज़न स्टेटमेंट- विकसित राजस्थान 2047 राजस्थान को 2047 तक भारत का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल पावरहाउस बनाने का सपना दिखा रहा है। यदि सरकार जीडीपी में कृषि का हिस्सा बढ़ाना चाहती है उसके लिए कोई तैयारी बजट के आंकड़ों में नज़र नहीं आती। सरकार के अब तक के सारे ईवेंट उद्योगपतियों और कारोबारियों के साथ हुए है जो ग्लेमर वाले हैं। पिछले दो सालों से औद्योगिक निवेश के तमाशों के बाद भी आर्थिक समीक्षा बताती है कि औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर मौजूद कीमतों पर 2023-24 में जो 13.61 प्रतिशत थी वह कम हो कर 2024-25 में 7.33 प्रतिशत रह गई और जिसके 2025-26 में गिर कर 6.99 प्रतिशत रह रही है। ग्रोथ के मामले में, खेती और उससे जुड़े सेक्टर ने साल 2025-26 में स्थिर (2011-12) कीमतों पर साल 2024-25 के मुकाबले मामूली 0.22 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की जिस पर इतराया नहीं जा सकता। साल 2025-26 के अनुमान के मुताबिक, राज्य में कुल अनाज का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 8.28 प्रतिशत कम है। किन्तु वित्त मंत्री ने कृषि बजट में इसका कोई जिक्र करना जरूरी नहीं समझा। यह तो माना गया है कि राजस्थान में बागवानी के विकास की बहुत गुंजाइश है क्योंकि यह गांव के लोगों को रोज़गार के अतिरिक्त मौके तो उपलब्ध कराती ही है, साथ ही गांव की अर्थव्यवस्था को एग्रो-प्रोसेसिंग और दूसरी सहायक गतिविधियों की ओर बढ़ाती है। मगर आर्थिक समीक्षा में यह विडंबना भी नज़र आती है कि साल 2025-26 (दिसंबर तक) के लिए, राज्य योजना के तहत रखे गये 1,918.67 करोड़ रुपये के बजट में से केवल 523.13 करोड़ रुपये का ही इस्तेमाल किया गया, जो प्रावधान का आधा भी नहीं है।

जब सकल घरेलू उत्पाद तेज़ी से बढ़े, लेकिन प्रति व्यक्ति आय उससे कम गति से बढ़े तो इसका सीधा अर्थ होता है कि राज्य की कुल अर्थव्यवस्था तो तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उस वृद्धि का लाभ हर व्यक्ति तक समान रूप से नहीं पहुंच रहा है। अर्थात आय का असमान वितरण हो रहा है। अगर आर्थिक वृद्धि का बड़ा हिस्सा उद्योगपतियों, बड़े कारोबारी समूहों तथा प्रशासनिक अमले तक सीमित रह जाए, तो आम लोगों की आय उतनी नहीं बढ़ती। यानी जीडीपी तो बढ़ता है, लेकिन आम आदमी की जेब नहीं भरती। इसे अर्थशास्त्री रोजगारविहीन विकास मानते हैं।

सरकार का ऋण लेकर राजस्व घाटा पूरा करना जारी है। मगर वित्त मंत्री ने अपने तीन घंटे लंबे भाषण में यह बात साफ-साफ नहीं कही। उनके पहले के वित्त मंत्री भी ऐसा ही करते रहे हैं। राजस्व घाटे का मतलब है कि सरकार के खर्चे, जैसे वेतन, सब्सिडी आदि उसकी कमाई से अधिक है। इस कारण राज्य का कुल राजकोषीय घाटा उसकी जीएसडीपी के लगभग 3.69 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया है, जो इसकी विधिक सीमा को छूने के करीब है। सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए बाजार से भी उधार लिया गया है। यह राजकोषीय घाटे और बॉरोविंग के आंकड़ों से स्पष्ट है। राजस्व घाटे को उधार लेकर संतुलित किया जाना राज्य की वित्तीय संरचना के कुछ गहरे कारणों और संभावित प्रभावों की ओर संकेत करता है। संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए इसका नियंत्रण आवश्यक माना जाता है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सब्सिडी आदि के अलावा पुराने कर्जों के ब्याज भुगतान का बढ़ता बोझ भी बजट घाटे का एक कारण है। यह कर्ज के चक्र में फंसने का संकेत है। आर्थिक गतिविधियों की मंद गति और लोकलुभावन योजनाएं भी घाटे को बढ़ाती हैं। लगातार राजस्व घाटा यह संकेत देता है कि राज्य अपनी दैनिक आय से अपने दैनिक खर्च पूरे नहीं कर पा रहा है। यह दीर्घकाल में वित्तीय स्थिरता के लिए चिंता का विषय हो सकता है। मगर यह पूरी तरह नकारात्मक भी नहीं होता है। यदि उधार का उपयोग उत्पादक निवेश में हो जिनसे आर्थिक गतिविधियां तेज़ हों तथा कर आधार बढ़े तो भविष्य में राजस्व बढ़ सकता है और घाटा नियंत्रित हो सकता है। लेकिन यदि ऋण मुख्यत: वेतन-सब्सिडी जैसे कामों में खर्च हो तो वह दीर्घकाल में जोखिमपूर्ण हो सकता है। वर्ष 2026-27 के बजट में राजस्व घाटा ऋण से संतुलित करना तत्कालीन वित्तीय आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह दीर्घकालीन समाधान नहीं है। इसके अलावा जीएसटी के बाद जब से सदन में कराधान सीमित हुआ है, तब वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन का महत्व और बढ़ गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य के लिए यह चुनौती बनी रहती है कि विकास, सामाजिक न्याय और वित्तीय स्थिरता- तीनों के बीच कैसे संतुलन बनाए रखा जाए। यहां सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय का रिश्ता समझने की जरूरत है। जब सकल घरेलू उत्पाद तेज़ी से बढ़े, लेकिन प्रति व्यक्ति आय उससे कम गति से बढ़े तो इसका सीधा अर्थ होता है कि राज्य की कुल अर्थव्यवस्था तो तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उस वृद्धि का लाभ हर व्यक्ति तक समान रूप से नहीं पहुंच रहा है। अर्थात आय का असमान वितरण हो रहा है। अगर आर्थिक वृद्धि का बड़ा हिस्सा उद्योगपतियों, बड़े कारोबारी समूहों तथा प्रशासनिक अमले तक सीमित रह जाए, तो आम लोगों की आय उतनी नहीं बढ़ती। यानी जीडीपी तो बढ़ता है, लेकिन आम आदमी की जेब नहीं भरती। इसे अर्थशास्त्री रोजगारविहीन विकास मानते हैं। बजट के आंकड़े बताते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था की बृद्धि पूंजी-प्रधान उद्योगों, या ऑटोमेशन से नहीं बल्कि रियल एस्टेट या वित्तीय सेक्टर से हो रही है, जहां रोजगार कम पैदा होता है, और आम लोगों की आय धीमी रहती है।ऐसा विकास समावेशी नहीं होता है तथा गरीबी और असमानता घटने की गति धीमी होती है।

राज्य विधान सभा में राज्यपाल का अभिभाषण और वित्तमंत्री का बजट भाषण दो ऐसे मौके होते हैं जब सरकार प्रदेश के विकास की अपनी दृष्टि सबे सामने रखती है। राज्यपाल का अभिभाषण जहां एक विहंगम दृष्टि देने का समय होता है वहीं बजट भाषण तथा अनुदान मांगें विभागीय स्तर पर सरकार के कामकाज की समीक्षा का मौका देती हैं। वित्त मंत्री के बजट भाषण के साथ ही विभिन्न विभागों के मंत्रियों द्वारा अनुदान मांगों पर बहस का के जवाब भी कम महत्वपूर्ण नहीं होते। इससे सरकार के सामूहिक दायित्व का भी प्रदर्शन होता है। मगर अब नई परंपराएं बनने लगी हैं। जो बातें संबंधित विभागों के मंत्रियों को कहनी चाहिए वह सभी बातें वित्त मंत्री खुद के लंबे भाषण में शामिल कर दी जाती है। अनुदान मांगों पर बहस के जवाब में संबंधित मंत्रियों द्वारा घोषणाएं करने का काम वित्त मंत्री ने खुद ही कर दिया। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में देश के प्रथम राष्ट्रपति को उद्धृत किया कि, लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा इस बात में है कि उसकी संस्थायें जनता की कितनी प्रभावी रूप से सेवा कर पाती हैं। मगर उनके बजट में पैसा खर्च करने की तो बातें थीं मगर उससे सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने का कोई रोडमैप नहीं था। और न ही मितव्ययता बरतने का सरकार का कोई इरादा दिखाया गया।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

विरासत का वैभव और विकास का विजन : बजट 2026-27

लक्ष्यराज सिंह मेवाड़

राजस्थान की पावन धरा ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध किलों और वैभवशाली महलों के साथ ही अदम्य साहस, अनुपम शौर्य और अक्षुण्ण सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। सदियों से अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने वाला यह प्रदेश अब विकास की एक नई इबारत लिख रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का 6,10,956 करोड़ का बजट विकसित राजस्थान @ 2047 के लक्ष्य को साकार करने की दूरदर्शी रूपरेखा है। इस बजट की आत्मा में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का कल्याण, पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन, लुप्त होती लोककलाओं का संरक्षण और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में परिलक्षित होती है। राजस्थान में पर्यटन आज अर्थव्यवस्था का सशक्त इंजन बन चुका है। वर्ष 2025 में प्रदेश ने 25.44 करोड़ घरेलू और विदेशी पर्यटकों का स्वागत कर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है।

'झीलों की नगरी' उदयपुर ने बीते आठ वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए 21.6 लाख पर्यटकों की मेजबानी की। इनमें 1.6 लाख से अधिक विदेशी सैलानी शामिल रहे। यह तथ्य प्रमाणित करता है कि मेवाड़ की सांस्कृतिक आभा और प्राकृतिक सौंदर्य का आकर्षण अब वैश्विक स्तर पर अपने चरम पर है।

इस बढ़ते पर्यटन प्रवाह को विश्वस्तरीय अनुभव में रूपांतरित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर 5,000 करोड़ के राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड की स्थापना एक ऐतिहासिक पहल है। यह निवेश न केवल पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता, सुरक्षा और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुविधाएं विकसित कर प्रदेश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को भी बढ़ाएगा। विकास की इस यात्रा में पर्यावरणीय संतुलन को समान महत्व देते हुए बजट में 'PRITHWI' (Project for Resilient and Integrated Terrestrial Habitats and Wildlife Valorization Initiative) के लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस पहल से स्पष्ट है कि सरकार विकास और प्रकृति के मध्य संतुलन को लेकर संवेदनशील है। वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ साझेदारी कर वन्यजीव उपचार केंद्रों की स्थापना वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करेगी।

विशेष रूप से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील में 'एविएन डिजीज ट्रीटमेंट सेंटर' की स्थापना से प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और विदेशी पर्यटकों के बीच राजस्थान की विश्वसनीयता और साख में वृद्धि होगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण को पर्यटन से जोड़ते हुए 'ईको-टूरिज्म' की अवधारणा को नई दिशा देने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बजट में वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साकार करते हुए पारंपरिक शिल्पकारों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का संकल्प भी दिखाई देता है। माटी कला के लिए 15 करोड़ का प्रावधान और 5 हजार इलेक्ट्रिक चाकों का वितरण केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जड़ों के पुनर्जीवन का सशक्त प्रयास है।

इसी क्रम में 200 करोड़ के विशेष कोष से 660 प्राचीन हवेलियों का जीर्णोद्धार हमारी वास्तु विरासत को संरक्षित करने की ऐतिहासिक पहल है। यह पर्यटन और सांस्कृतिक गौरव को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

थार की स्वर्णिम रेत में बसे जैसलमेर के खुड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित अल्ट्रा-लक्जरी स्पेशल टूरिज्म ज़ोन राजस्थान को वैश्विक लक्जरी पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में साहसिक कदम है। यह परियोजना उच्चस्तरीय आतिथ्य सेवाओं, विशिष्ट अनुभवों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के समन्वय से राज्य को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाएगी।

पर्यटन की सफलता का आधार केवल आकर्षण नहीं, बल्कि सुगम पहुंच भी है। 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' को सुदृढ़ करते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों तक सहज परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही, प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ने के उद्देश्य से DORA (Domestic and Overseas Rajasthani Affairs) विभाग का विस्तार एक सशक्त 'सॉफ्ट पावर' रणनीति है। यह सांस्कृतिक संवाद और निवेश की संभावनाओं को विस्तृत करेगा।

यह बजट विकास और विरासत के अद्वितीय समन्वय का दस्तावेज है। एक लाख नई सरकारी भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी करना और निजी व पर्यटन क्षेत्र में सृजित होने वाले लाखों अप्रत्यक्ष रोजगारों के माध्यम से होने वाला आर्थिक सशक्तिकरण समग्र विकास की दिशा में ठोस कदम सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी कार्यशैली में विकास का रथ सचमुच विरासत के पहियों पर सवार होकर आगे बढ़ रहा है। यह बजट राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को आर्थिक शक्ति में रूपांतरित करने की ऐतिहासिक पहल है, जिसे आने वाली पीढ़ियां एक स्वर्णिम युग के सूत्रपात के रूप में स्मरण करेंगी।

-लक्ष्यराज सिंह मेवाड़

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) और भारत में रोजगार का भविष्य

राम शर्मा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई) आज दुनिया के सबसे तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी क्षेत्रों में से एक है। यह तकनीक न केवल वैज्ञानिक शोध और तकनीकी उद्योगों को प्रभावित कर रही है, बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और शासन जैसे बुनियादी सामाजिक स्तंभों को भी गहराई से बदल रही है। इसी संदर्भ में इंडिया 2026, जो नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16-21 फरवरी 2026 तक आयोजित हई, एक ऐतिहासिक वैश्विक मंच साबित हुआ है।

यह समिट पहली बार एक उर्दैत एदल्प देश-भारत द्वारा आयोजित वैश्विक एआइ सम्मेलन था, जिसमें लगभग 100 से अधिक देशों, शीर्ष तकनीकी कंपनियों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और उद्योग जगत के नेताओं ने भाग लिया। इसे एआइ और मानव-केंद्रित भविष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम के रूप में देखा गया।

एआइ की प्रगति ने पारंपरिक तौर पर कार्य करने वाले ढांचों को चुनौती दी है। मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स और स्वचालित प्रणालियों के उदय ने कुछ क्षेत्रों में मानव श्रम की आवश्यकता को कम किया है, जबकि कुछ क्षेत्रों में नई भूमिकाओं का सृजन भी किया है। उदाहरण के लिए, डेटा वैज्ञानिक, एआइ इंजीनियर, एआइ नैतिकता विशेषज्ञ, और मशीन लर्निंग ऑपरेशन्स (MLOps) इंजीनियर जैसे नए पेशे उभर कर सामने आए हैं।

एआइ का प्रभाव सिर्फ तकनीकी कर्मियों तक सीमित नहीं रहता; यह स्वास्थ्य सेवा में रोग निदान और उपचार सुझावों, कृषि में बेहतर पैदावार प्रबंधन, शिक्षा में व्यक्तिगत सीखने के तरीकों, और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता एवं दक्षता जैसे क्षेत्रों तक फैल चुका है। भारत जैसे देश में जहां युवा आबादी की संख्या अधिक है, एआइ के रोजगार प्रभाव पर संतुलन बनाना आगे की विकास रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नीति निर्माताओं का मानना है कि एआइ की क्षमता का विस्तार तभी सफल होगा जब कौशल विकास और रोजगार सुरक्षा को एक साथ जोड़कर काम किया जाए।

इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन इंडिया एआई मिशना के अंतर्गत किया गया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। इस समिट का विषय सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय - सबके हित और सुख के लिए एआइ रखा गया था। यह यह संकेत देता है कि एआइ सिर्फ तकनीकी अचीवमेंट नहीं बल्कि सामाजिक समावेशन और मानव-केंद्रित प्रगति का हिस्सा भी है। एआइ समिट में 300 से अधिक प्रदर्शकों के साथ विभिन्न -आधारित उत्पादों, समाधान और मॉडल को प्रदर्शित किया गया। इनमें भारतीय स्टार्टअप और शोधशालाओं द्वारा विकसित मॉडल जैसे मल्टी-भाषी, स्मार्ट ग्लासेस और भाषण पहचान प्रणालियां शामिल थीं, जिनका लक्ष्य भारत के बहुभाषी एवं विविध समाज की जरूरतों को पूरा करना था।

नई दिल्ली घोषणा और वैश्विक सहयोग: सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट पर 80 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए यह घोषणा वैश्विक स्तर पर एआई के विकास को नैतिक, पारदर्शी और समावेशी बनाने पर जोर देती है. इसमें यह स्पष्ट किया गया कि एआई को समाज के व्यापक हित में उपयोग किया जाए, जिससे आर्थिक असमानताएं कम हों और तकनीक के लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे। यह पहल वैश्विक समुदाय को यह संदेश देती है कि एआई सिर्फ तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साझा वैश्विक जिम्मेदारी भी है।

रोजगार के अवसर बनाम जोखिम: एआई के रोजगार पर प्रभाव को लेकर दो मुख्य दृष्टिकोण सामने आते हैं, पहला: उच्च-स्तरीय कुशल कार्यों की मांग: एआई और डेटा-आधारित भूमिकाएं नए कौशल वाले पेशेवरों की मांग बढ़ा रही हैं। यह भारत जैसे युवा-जनसंख्या वाले देश के लिए अवसर की बात है, जहां तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर फोकस किया जा सकता है।

सामान्य और पारंपरिक नौकरियों का जोखिम: पहले से स्थापित रूटीन और दोहराए जाने वाले कार्य जैसे डेटा एंट्री, प्राथमिक ठाहक सेवा आदि पर एआई आधारित ऑटोमेशन का असर देखा जा रहा है। इससे कुछ पारंपरिक नौकरियां कम हो सकती हैं, जिससे कौशल रिस्किलिंग की आवश्यकता और बढ़ जाएगी। समिट ने इन दोनों पहलुओं पर गंभीर बहस की और यह निष्कर्ष निकाला कि भारत को एआई रेडी वर्कफोर्स तैयार करनी होगी, जिसमें अकादमिक संस्थान, उद्योग और सरकार मिलकर काम करें। शिक्षा पाठ्यक्रम में एआई और डेटा-साइंस जैसे विषयों को शामिल करना, और व्यापक स्तर पर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना आवश्यक बताया गया। भारत की युवा आबादी एआई-आधारित रोजगार और स्टार्टअप संभावनाओं के लिए एक बड़ा स्त्रोत है। समिट के दौरान निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भारत में आधारित नवाचारों और स्टार्टअपों में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। देश के डिजिटल ढांचे, मजबूत आइटी पारिस्थितिकी तंत्र, और बुनियादी एआइ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजना (मिलियन-प्लस GPU साझा संसाधन) ने निवेश के दृष्टिकोण को और आकर्षक बनाया है। एआई तकनीक जैसे भाषा-आधारित मॉडल, बोली-पहचान प्रणालियां, स्वास्थ्य और कृषि-समाधान ने यह दिखाया है कि एआई का उपयोग सिर्फ तकनीकी डोमेन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के रोज़मर्रा जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। एआइ का भविष्य अत्यंत विशाल है और रोजगार के परिदृश्य में यह एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है।

समिट ने स्पष्ट किया कि एआइ सिर्फ रोजगार को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि रोजगार की प्रकृति को बदल रहा है। यह तकनीक उन नौकरियों की मांग बढ़ा रही है जहां तकनीकी दक्षता, विश्लेषणात्मक सोच और नवाचार कौशल की आवश्यकता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये चुनौतियां और अवसर दोनों हैं। सरकारी नीतियां जिस तरह AI-ready शिक्षण, कौशल विकास, और रोजगार-अनुकूल वातावरण बना रही हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि भारत एआइ युग में सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक नेता और नवप्रवर्तन केंद्र बन सकता है। एआइ और रोजगार का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कैसे अपनी युवा शक्ति को एआइ-समर्थ कौशल से लैस करते हैं, और कैसे एआइ के विकास को नैतिकता, समावेशन और सामाजिक लाभ के लक्ष्यों के साथ जोड़ते हैं।

- राम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हाई इंटेंसिटी सैन्य अभ्यास "खड़ग शक्ति-2026" संपन्न

युद्धाभ्यास में ड्रोन स्वार्म, हैवी आर्टिलरी और अपाचे रुद्र ने सटीक प्रहार कर स्ट्राइक क्षमता दिखाई

बीकानेर, (निसं)। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पश्चिमी कमान का हाई इंटेंसिटी सैन्य अभ्यास "खड़ग शक्ति-2026" दमदार प्रदर्शन के साथ संपन्न हो गया। पहली बार "चक्रव्यूह" रणनीति रचकर दुश्मन के ठिकानों पर समन्वित प्रहार का लाइव सिमुलेशन किया गया। टैंक, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की गूंज से थार का रेगिस्तान थर्रा उठा।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे पश्चिमी कमान का अब तक का सबसे बड़ा और तकनीक आधारित कॉम्बैट ड्रिल माना जा रहा है। अभ्यास में नेटवर्क केंद्रित युद्ध, ड्रोन ऑपरेशन्स, एयरबोर्न क्षमता और इंटीग्रेटेड फायर पावर का व्यापक प्रदर्शन हुआ। अभ्यास के समापन चरण में पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर मनोज कुमार कटियार और कोर कमांडर राजेश पुष्कर मौजूद रहे। उनके समक्ष आर्टिलरी फायर, एयरबोर्न ऑपरेशन्स और संयुक्त युद्धाभ्यास के जरिए वास्तविक युद्धक्षेत्र का सजीव सिमुलेशन किया गया। 8 से 10 हजार फीट की ऊंचाई से सैनिकों को कॉम्बैट लोड के साथ पैराड्रॉप कर त्वरित तैनाती और तत्काल प्रतिक्रिया क्षमता का प्रदर्शन किया गया। अभ्यास में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों ने सटीक प्रहार कर अपनी स्ट्राइक क्षमता दिखाई। स्वदेशी रुद्र (एएलएच-डब्ल्यूएसआई) हेलीकॉप्टर ने एयर ग्राउंड कोऑर्डिनेशन का प्रभावी प्रदर्शन किया। "खड़ग शक्ति-2026" में ड्रोन को केंद्रीय भूमिका दी गई। "खड्गा" और "ऐरावत" जैसे स्वदेशी ड्रोन तथा टेथर्ड ड्रोन के जरिए लक्ष्य पहचान, निगरानी और समन्वित हमले की रणनीति प्रदर्शित की गई। ड्रोन स्वार्म ने आधुनिक युद्ध में निर्णायक भूमिका का प्रदर्शन किया। लॉजिस्टिक ड्रोन ने करीब 200 किलोग्राम भार उठाकर भविष्य के युद्धक्षेत्र में आपूर्ति प्रणाली की नई संभावनाएं दर्शाई। सैनिकों को काउंटर यूएवी रणनीति, मल्टी लेयर एयर डिफेंस और ड्रोन हमलों से बचाव का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। रात्रिकालीन चरण में नाइट आर्टिलरी फायरिंग, रॉकेट लॉन्चर ऑपरेशन्स और उन्नत हथियार प्रणालियों के साथ युद्ध तैयारी का मूल्यांकन किया गया।

- **"खड्गा" और "ऐरावत" जैसे स्वदेशी ड्रोन तथा टेथर्ड ड्रोन के जरिए लक्ष्य पहचान, निगरानी और समन्वित हमले की रणनीति प्रदर्शित की गई**

अभ्यास में बख्तरबंद और यंत्रीकृत इकाइयों के साथ पैदल सेना ने दुश्मन के मोर्चों पर समन्वित तरीके से हमला करने की रणनीति दिखाई। सैनिकों को नजदीकी मुकाबले, शहरी युद्ध और ड्रोन सहायता प्राप्त ऑपरेशन्स के लिए प्रशिक्षित किया गया। अभ्यास के दौरान थल, वायु, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को एकीकृत करते हुए मल्टी डोमेन ऑपरेशन्स की व्यापक परीक्षा की गई। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, इंटेलिजेंस और सर्विलांस सिस्टम के जरिए पूरे युद्धक्षेत्र में त्वरित निर्णय और नियंत्रण क्षमता का प्रदर्शन किया गया। "खड़ग शक्ति-2026" भारतीय थलसेना की आधुनिक, तकनीक आधारित और नेटवर्क-केंद्रित युद्ध तैयारी का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। महाजन रेंज में हुआ यह अभ्यास भविष्य के युद्ध परिदृश्य के लिए सेना की तत्परता और सामरिक क्षमता का मजबूत संदेश देता है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 25 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, रोहिणी नक्षत्र दिन 1:39 तक, विष्कुम्भ योग रात्रि 1:29 तक, बालव करण दिन 3:46 तक, चन्द्रमा रात्रि 12:55 से मिथुन राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-वृष, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। ज्वालामुखी योग दिन 1:39 तक है। रवियोग दिन 1:39 से आरम्भ होगा। आज आनन्दा नवमी, श्री हरि जयन्ती है। आज से ब्रज में होली आरम्भ है। बरसाना में होली और रोहिणी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:50 तक, शुभ 11:15 से 12:40 तक, चर 3:31 से 4:56 तक, लाभ 4:56 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:59, सूर्यास्त 6:21

मेष

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृष

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन

आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि होने का भय है। अनावश्यक धन खर्च होगा। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

कर्क

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव रहेगा।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

कन्या

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

तुला

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत ब